भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3026

22 मार्च, 2022 को उत्तरार्थ

सहकारिता के लिए नई नीति

3026. श्री एस. जगतरक्षकन :

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि सहकारी समितियों के लिए आगामी नई नीति तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; तथा

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क): जी हां।

(ख) और (ग): सहकारिता मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों की सहकारी समितियों पर सूचना के लिए एकल बिंदु पहुंच प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस बनाने की प्रक्रिया शुरू की है जो सहकारी समितियों की समय उपयोगी नीति बनाने में सुविधा प्रदान करेगी। मंत्रालय ने डेटाबेस में विभिन्न मापदंडों, क्रियाविधियों और प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श शुरू कर दिया है।

*****